

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 04

अंक - 24

जौनपुर

शनिवार, 06 सितम्बर 2025

साप्ताहिक (संस्करण)

पेज - 4

मूल्य - 2 रुपये



सीएम योगी ने, 2251 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण



गोरखपुर, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे। जहां जनपद गोरखपुर के गीडा क्षेत्र में 2251 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के लोकार्पणधिलान्यास किया। साथ

ही गीडा आवासीय योजना, औद्योगिक योजना के भूखंडों के आवंटन-पत्र वितरण हेतु आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जनता दर्शन में 250 लोगों की समस्याएं सुनीं सीएम योगी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हर पात्र व्यक्ति को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए। जरूरतमंदों के इलाज से लेकर आवास तक की व्यवस्था के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ बढ़े पैमाने पर दिया जा रहा है। पर, किन्हीं कारणों से यदि कोई व्यक्ति इन योजनाओं के दायरे में अभी नहीं आ पाया हो तो उसे भी योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रभावी कार्यवाही की जाए।

सीएम योगी ने ये निर्देश गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं

सुनते हुए दिए। मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में कुर्सियों पर बैठे गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक करके सबकी समस्याओं को सुनते हुए आश्वस्त किया हर समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी व संतुष्टिपरक निस्तारण किया जाएगा।

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 250 लोगों की समस्याएं सुनीं। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की रही। इस दौरान एक महिला ने उसके आवास निर्माण के दौरान कुछ लोगों द्वारा लिंटर डालने में बाधा उत्पन्न

करने की समस्या बताई। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला की मदद की जाए और यदि कोई विधि विरुद्ध बाधा डाल रहा हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी तरह जमीन कब्जा करने की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। राजस्व व पुलिस से संबंधित मामलों में प्रभावी कार्यवाही हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

बिहार भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में अमित शाह की नसीहत

पटना, (एजेंसी)। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके लिए राजनातिक पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारी तेज कर दी है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में प्रदेश के नेताओं को बेवजह की बयानबाजी से बचने और विपक्षी महागठबंधन के मुद्दों के खिलाफ जमीनी स्तर पर सक्रिय अभियान चलाने की नसीहत दी है। कोरग्रुप की बैठक में शाह ने साफ कर दिया है कि इस बार उम्मीदवारों के चयन में स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावनाओं को पहली प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने राज्य इकाई

को जल्द से जल्द चुनाव अभियान समिति गठित करने सभी विधानसभा सीटों पर सक्रियता बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। बुधवार को करीब चार घंटे



बैठक में विपक्षी महागठबंधन की ओर से एसआईआर के खिलाफ जारी अभियान की काट पर बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश के नेताओं को जीएसटी दर में

परिवर्तन के कारण नवरात्र से गरीबों और मध्य वर्ग को मिलने वाली राहत का जोरशोर से प्रचार करने का निर्देश दिया गया। सूत्रों ने बताया कि शाह ने उम्मीदवारों के चयन के लिए विधानसभा स्तर पर प्रदेश नेतृत्व के साथ मिल कर कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप सूची तैयार करने का निर्देश भी दिया। बैठक में तय किया गया कि 25 सितंबर तक हर विधानसभा सीट पर कार्यकर्ता स्तर के सम्मेलन का काम हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। दूसरे राज्यों के चुनाव की तरह ही बिहार में भी पार्टी हर छह विधानसभा के लिए एक प्रमारी नियुक्त करेगी।

संक्षिप्त खबरें

कोर्ट ने रेलवे के पूर्व कर्मचारी को रिश्वतखोरी के मामले में किरा बरी

ठाणे, (एजेंसी)। ठाणे की एक विशेष सीबीआई अदालत ने रेलवे के एक पूर्व प्वाइंटमैन को 18 साल पुराने रिश्वतखोरी के मामले में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी को खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। कोर्ट ने यह फैसला दो दिसंबर को दिया, जिसकी प्रति आज उपलब्ध कराई गई। विशेष सीबीआई जज डी. एस. देशमुख ने शिवाजी श्रीपत मशाल के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कल्याण रेलवे स्टेशन के तत्कालीन स्टेशन मास्टर ओमप्रकाश तिपन्ना निन्ने ने एक बूट पॉलिश ठेकेदार से हर महीने 1,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। ठेकेदार ने सीबीआई को इसकी सूचना दी, जिसके बाद दो मार्च 2007 को सीबीआई ने जाल बिछाया और मशाल को पैसे लेते हुए पकड़ा, जो कथित रूप से निन्ने की ओर से रिश्वत ले रहे थे। अदालत ने माना कि मशाल के खिलाफ रिश्वत मांगने या लेने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। उस दिन मशाल को स्टेशन मास्टर निन्ने के दफ्तर में अस्थायी रूप से तैनात किया गया था क्योंकि नियमित चपरासी छुट्टी पर था। शिकायतकर्ता और निन्ने की मुकदमे में सुनवाई के दौरान मौत हो गई। अदालत ने अभियोजन पक्ष के दो गवाहों से पूछताछ की, लेकिन उनके बयान से मामले को कोई मजबूती नहीं मिली। जज देशमुख ने यह भी बताया कि खुद सीबीआई ने यह मामला वापस लेने की अर्जी दी थी, क्योंकि मामले में कई समस्याएं थीं। शिकायतकर्ता और मुख्य आरोपी अब जीवित नहीं हैं और न तो शिकायत में और न ही सीबीआई की जांच में मशाल को रिश्वत लेने वाला बताया गया है। जज ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि मशाल ने (मृतक) स्टेशन मास्टर की ओर से 1,000 रुपये की रिश्वत ली थी।

जरूरी वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए- अवधेश प्रसाद

अयोध्या, (एजेंसी)। यूपी के अयोध्या में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जीएसटी संशोधन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में जीएसटी में राहत देना चाहती है तो सबसे पहले किसानों पर लग रहे कर को हटाए। किसान आज भी खाद, कीटनाशक और कृषि यंत्रों पर जीएसटी चुकाने के लिए मजबूर हैं। यह उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ है, जबकि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के दावे करती है। सांसद ने कहा कि इस संशोधन से आम जनमानस को कोई राहत नहीं मिल रही है। यदि सरकार की नियत साफ है तो उसे उन वस्तुओं पर जीएसटी हटाना चाहिए, जिनका उपयोग आम लोग करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल दिखावा कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि गरीब और किसान लगातार परेशान हैं। अवधेश प्रसाद ने अफसोस जताते हुए कहा कि इस सरकार में तो कफन पर भी जीएसटी लगाया गया है। यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में करीब 90 करोड़ लोग राशन पर निर्भर हैं, लेकिन इस जीएसटी संशोधन से उनकी आर्थिक हालत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार को ईमानदारी से किसानों और गरीब वर्ग के लिए कदम उठाने चाहिए। जरूरी वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए।

सरकार में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं : संजय राउत

मुंबई, (एजेंसी)। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें सरकार में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राउत का यह बयान उस वीडियो के सामने आने के बाद आया है, जिसमें अजित पवार एक महिला आईपीएस अधिकारी को फोन पर फटकार लगाते दिखाई दे रहे हैं। यह मामला सोलापुर जिले में अवैध मुर्तम मिट्टी की खुदाई से जुड़ा है। संजय राउत ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अजित पवार चोरी करने वालों को बचाने का काम कर रहे हैं और अदिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो नेता जनता को कानून का पालन करने की



सीख देते हैं, वही अधिकारियों को गैरकानूनी काम में मदद करने का आदेश दे रहे हैं। राउत ने सवाल किया कि कहां है उनकी अनुशासन की बात? सामने आए वीडियो में देख रहा है कि अजित पवार महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा को फोन पर फटकार लगाते हैं। यह फोन कॉल एनसीपी के एक कार्यकर्ता के फोन से किया गया था। अधिकारी शुरुआत में पवार की आवाज नहीं पहचानतीं, जिसके बाद उपमुख्यमंत्री वीडियो कॉल करते हैं और उनसे कार्रवाई रोकने के लिए कहते हैं। पवार उन्हें सख्त लहजे में सवाल करते हैं कि क्या वे उनका चेहरा पहचानती हैं। अवैध मुर्तम खुदाई का मामला

जुआ युवाओं और परिवारों को बर्बाद कर रहा था-पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने वाला नया कानून बिना किसी देबाव के लागू किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गेमिंग बुरा नहीं है, लेकिन जुआ युवाओं और परिवारों को बर्बाद कर रहा था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के साथ संवाद में कहा कि शॉनलाइन गेमिंग प्रचार और विनियमन अधिनियम, 2025' छात्रों और परिवारों को लत, आर्थिक शोषण और हिंसक सामग्री से बचाने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत सभी तरह के ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक रहेगी, जबकि ई-स्पोर्ट्स और सकारात्मक ऑनलाइन गेम्स को प्रोत्साहित किया



जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत यदि सही दिशा में प्रयास करे तो वैश्विक ऑनलाइन गेमिंग बाजार पर प्रभुत्व जमा सकता है, साथ ही इसमें रोजगार की भारी संभावनाएं भी हैं। पीएम मोदी ने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे छात्रों को गेमिंग और जुए के अंतर के बारे में जागरूक करें। प्रधानमंत्री ने बताया कि कई लोग, खासकर युवा और गृहिणियां,

ऑनलाइन जुए में फंसकर कर्ज और आत्महत्या जैसे खतरनाक हालात तक पहुंच रहे थे। पीएम मोदी ने आगे इस बात पर जोर दिया कि आखिर क्यों ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ा। इस बात पर उन्होंने कहा कि यह एक नशे की तरह फैल रहा था, इसलिए सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा। उन्होंने नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर भी

बल दिया। पीएम मोदी ने बताया कि देशभर में 10,000 से अधिक अटल टिकरिंग लैब्स स्थापित हो चुकी हैं और 50,000 नई लैब्स मंजूर की गई हैं। कहा, शिक्षक आने वाली पीढ़ी को जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जताते हुए कहा कि ऑनलाइन जुए ने कई परिवारों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, महिलाएं और युवा इसकी चपेट में आए हैं और कई मामलों में लत इतनी गंभीर हो गई कि आत्महत्या तक की नौबत आ गई। सरकार अब ऐसे खतरों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने आगे शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को इस लत से बचाएं और समझाएं कि ऑनलाइन गेमिंग कैसे जिम्मेदारी से की जाए।

मेरी गाड़ी का आठ लाख का चालान वसूली कर रही है पुलिस : अखिलेश यादव

लखनऊ, (संवाददाता)। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार जनता से वसूली कर रही है। सुविधाएं नहीं दे रही हैं लेकिन जमकर टैक्स वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी का ओवर स्पीडिंग के कारण आठ लाख रुपये का चालान कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग पूरा सिस्टम चला रहे हैं। पुलिस पैसा वसूल रही है। सरकार की तरफ से जो गाड़ी हमें दी गई है वो चलने की हालत में नहीं है। अखिलेश यादव शुक्रवार को लखनऊ में सपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जीएसटी की दरों में बदलाव पर कहा कि ये सब चुनाव को देखकर किया गया है। मुनाफाखोरी कम नहीं हो रही है। ट्रंप के टैरिफ ने भाजपा के लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है। मेक इन इंडिया की बात करने वाले लोग हमारे बाजारों में चीन का माल भर दे रहे हैं। चीन का सामान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को पूरी तरह खत्म कर देगा। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि जुगाड़ आयोग भाजपा के लिए वोटों का इंजाम कर रहा है। अब उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। ये लोग देश के साथ धोखा कर रहे हैं। जब जुगाड़ आयोग ही धोखा करे तो लोग कहां जाएं। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा सरकार के अब गिनती के दिन ही बचे हैं। ये जल्दी ही जाने वाले हैं। कहा कि प्रधानी के चुनाव में बिल्कुल भी वोट चोरी नहीं हो पाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना अपमानजनक है। इस सरकार में सभी लोग दुखी हैं। हर जगह भ्रष्टाचार और वसूली हो रही है।



राज्य सरकार के बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव कराने के फैसले का भाजपा ने किया विरोध

बंगलूरु, (एजेंसी)। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार राज्य में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से करवाने जा रही है। राज्य सरकार के इस फैसले की भाजपा ने विरोध किया है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए विपक्षी भाजपा ने शुक्रवार को दावा किया कि अगले स्थानीय निकाय चुनावों में ईवीएम के बजाय मतपत्रों का उपयोग करने का राज्य मंत्रिमंडल का फैसला इस बात का षड-प्रमाण है कि सत्तारूढ़ पार्टी वोट चोरी के माध्यम से सत्ता में आई है। कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) से यह सिफारिश की थी कि कर्नाटक में भविष्य में होने वाले सभी पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के बजाय मतपत्रों का उपयोग करके कराए जाएं। कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने ईवीएम में जनता के विश्वास और विश्वसनीयता में कमी के कैंबिनेट के फैसले का कारण बताया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने आरोप लगाया, उन्हें फिर से मतपत्रों का उपयोग करके चुनाव जीतने दें या स्वीकार करें कि वे वोट चोरी के माध्यम से सत्ता में आए हैं। विजयेंद्र ने एक्स पर लिखा कि, देश में सबसे अधिक अवैध मतदान, वोट चोरी की शिकायतें चुनावी हिंसा की घटनाएं और अनियमितताओं की शिकायतें बैलेट पेपर पर हुए चुनावों के दौरान अदालतों में दर्ज की गई हैं और वो भी कांग्रेसियों के खिलाफ।



राहुल गांधी ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, रायबरेली में राजधानी एक्सप्रेस के स्टॉपेज की मांग

नई दिल्ली . (एजेंसी)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सीट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने रायबरेली के स्थानीय लोगों की लंबित मांग का हवाला देते हुए रायबरेली जंक्शन पर डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के उतराव की मांग की है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि यह ट्रेन पहले से ही रायबरेली से होकर गुजरती है। उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली के लोग इस स्टेशन पर ट्रेन के उतराव की



लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं ताकि राष्ट्रीय राजधानी के लिए उनकी यात्रा आसान हो सके। अपने पत्र में राहुल गांधी ने रेलमंत्री से रायबरेली जंक्शन पर ट्रेन संख्या 20503&20504 और ट्रेन संख्या 20505&20506 के उतराव की मांग पर विचार करने का अनुरोध किया है। राहुल गांधी ने लिखा कि मेरे संसदीय क्षेत्र

रायबरेली के लोग बार बार इस ट्रेन के उतराव की मांग करते रहे हैं खासकर नई दिल्ली की यात्रा को सुगम बनाने के लिए। यह मांग लंबे समय से लंबित है और इसे पूरा करने से उनके क्षेत्र के लोगों की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। दरअसल, रायबरेली के लोग लंबे समय डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के उतराव की मांग कर रहे थे। लोगों की परेशानी और उनके मांग को देखते हुए क्षेत्रीय सांसद राहुल गांधी ने रेलमंत्री को पत्र लिख स्टॉपेज देने की मांग की है ताकि रायबरेली के लोग भी इस ट्रेन में सफर कर सकें।

संपादकीय

राहतकारी जीएसटी

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद घोषित जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू करने करने की घोषणा की गई है। जिसमें अब 12 व 28 फीसदी के दो स्लैब को खत्म करके सिर्फ 5 व 18 फीसदी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह सरकार की ओर से आर्थिक सुधारों की कड़ी में एक नई पहल है, जिससे जीएसटी को तार्किक बनाने व आम जनता को महंगाई से राहत देने का प्रयास है। वहीं दूसरी ओर विलासिता आदि वस्तुओं के लिये चालीस फीसदी का एक नया स्लैब जोड़ा गया है। विपक्ष इसे देर से उठाया गया कदम बता रहा है, तो सरकार आर्थिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम। वहीं कुछ अर्थशास्त्री इस कदम को ट्रंप के टैरिफ वॉर के परिप्रेक्ष्य में उठाया गया सुरक्षात्मक कदम मानते हैं। जिससे घरेलू खपत को बढ़ाकर निर्यात घाटे को कम किया जा सके। वहीं कुछ लोग इसे नवरात्र में दिवाली से पहले सरकार का तोहफा बता रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार की सोच है कि आर्थिक सुधारों के जरिये घरेलू उपभोग व निवेश को बढ़ाया जाए। निस्संदेह, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। यही वजह है कि कुछ अर्थशास्त्री जीएसटी दरों को घटाने को साहसी व दूरदर्शी कदम बताते हैं, जो उपभोक्ता के उपभोग को बढ़ाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने एक जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू किया था। उसके बाद समय-समय पर विभिन्न उत्पादों की दरों में परिवर्तन किए जाते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों द्वारा शासित सरकारें कई उत्पादों पर जीएसटी दरें तार्किक बनाने की मांग करती रही हैं। जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर घटाने की मांग की थी। इतना ही नहीं, कुछ उद्योगों, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों व जन-स्वास्थ्य से जुड़ी वस्तुओं के उत्पादकों द्वारा जीएसटी कम करने की मांग की जाती रही है। इसी तरह किसान संगठन भी कृषि उत्पादों पर कर कम करने की मांग करते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जीएसटी दरों में बदलाव की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। उनका मानना है कि इसकी पृष्ठभूमि में ट्रंप के टैरिफों को कम करने की कवायद भी है ताकि घरेलू उपभोग बढ़ाया जा सके और सस्ते निर्यात को बढ़ावा मिल सके। कालांतर इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिल सकेगी। इसका संकेत प्रधानमंत्री ने पंद्रह अगस्त को लाल किले से संबोधन में भी दिया था। वहीं आगामी वर्ष मार्च में राज्यों को राहत देने वाले कम्पेंशन सेस की समाप्ति से पहले राज्यों को राहत देने के लिये भी यह कदम उठाया गया हो सकता है। निस्संदेह, इस कदम से सरकारी खजाने में जीएसटी कम आएगा, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि विलासिता की वस्तुओं पर चालीस फीसदी का जीएसटी सरकार के घाटे की पूर्ति में किसी हद तक मदद करेगा। फिर भी कहा जा रहा है कि सरकार को अड़तालीस हजार करोड़ का नुकसान हो सकता है, लेकिन चीजें सस्ती होने पर उपभोग वृद्धि से सरकार को राहत मिल सकती है। वहीं कहा जा रहा है कि असंगठित क्षेत्र को जीएसटी कटौती दर का लाभ नहीं मिलेगा। अर्थशास्त्री लंबे समय से मांग करते रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले असंगठित क्षेत्र को आर्थिक सुधारों का लाभ दिया जाना चाहिए। बहरहाल, इतना तय है कि जीएसटी दरों में कमी से उपभोक्ता मांग में वृद्धि होगी तो अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। आम आदमी कम पैसे में ज्यादा सामान खरीद पाएगा।

बौद्धिक पूंजी की समृद्धि के लिए प्रेरक योगदान

मयांक शिक्षक का कार्य मेंटोरिंग, शोध का मार्गदर्शन, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहन, और समाज की प्रगति में योगदान देने वाले मूल्यों को स्थापित करना भी है। यदि उन्हें उचित वेतन और सम्मान नहीं मिलता, तो यह न केवल उनकी व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि यह राष्ट्र की बौद्धिक पूंजी को भी कमजोर करता है। भारत की विद्यालय शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। जहां 15 लाख विद्यालयों में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियों से आने वाले 25 करोड़ बच्चों को 95 लाख शिक्षक पढ़ाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास



सूचकांक रिपोर्ट (2023-24) के अनुसार, भारत में स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष 6.6 वर्ष है। वहीं यह औसत विकसित देशों में लगभग 14 वर्ष है, वैश्विक स्तर पर यह 8.7 वर्ष है। इसका मतलब है कि एक औसत स्कूली शिक्षा प्राप्त करता है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि शिक्षा तक पहुंच और उसकी गुणवत्ता को और बेहतर करने की आवश्यकता है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि वर्तमान में देशभर के स्कूलों में लगभग 11.6 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हैं क्योंकि

भर्ती और प्रतिधारण में कई संरचनात्मक कठिनाइयां हैं। भारत में अध्यापन व्यवसाय के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जिनमें योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, शिक्षा संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, तकनीकी एवं नवाचारों के प्रति वैचारिक जकड़न, सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंताएं, कार्यभार के सापेक्ष कम वेतन, तनाव, बर्नआउट और निराशाजनक कार्य-संस्कृति शामिल हैं, जो सरकारी स्कूलों में अनुपस्थिति और प्रॉक्सी शिक्षण को बढ़ावा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को अक्सर अलगाव और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि निजी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों

को प्रतिस्पर्धी दबाव और असुरक्षित भविष्य के साथ अपर्याप्त वेतन पर कार्य करना पड़ता है। विभिन्न नियामक एवं विधायी निकायों के रहते हुए भी यह विषमतापूर्ण हालात स्कूली शिक्षा में ही नहीं, उच्च शिक्षा, भारतीय अपने जीवन में औसतन केवल 6.6 वर्ष तक औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करता है। यह व्यक्तिगत रूप से शिक्षा तक पहुंच और उसकी गुणवत्ता को और बेहतर करने की आवश्यकता है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि वर्तमान में देशभर के स्कूलों में लगभग 11.6 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हैं क्योंकि

को भगवान के समान कहना ही काफी नहीं है, यह राष्ट्र के उनके प्रति व्यवहार में भी झलकना चाहिए। ज्ञान-आधारित समाज से पारिभाषित देश में न्यायालय की यह टिप्पणी विचारणीय है कि समाज को शिक्षकों के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। गुरु-गोविन्द से अलंकृत शिक्षकों को उचित वेतन, बेहतर कार्यस्थल, प्रशिक्षण के अवसर, और सामाजिक सम्मान प्रदान करना प्राथमिक कार्य होना चाहिए। शिक्षक केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि देश के भविष्य को आकार देते हैं। इसी कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सफल क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। गौरतलब है कि आठवें वेतन आयोग की दहलीज पर खड़े हुए शिक्षक को अकुशलकर्मों के लिए निर्धारित मानदेय के बराबर पारिश्रमिक दिया जा रहा है। निजी क्षेत्र में कार्यरत प्राथमिक शिक्षक का मासिक वेतन सरकारी शिक्षकों की तुलना में 36 प्रतिशत कम है। निजी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों को औसतन 11,086 रुपये मिलते हैं। यही हाल माध्यमिक स्तरीय शिक्षकों का है, जहां उन्हें औसतन 13,412 रुपये मिलते हैं जो कि सरकारी शिक्षकों की तुलना में केवल 35 प्रतिशत है। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी चिंताजनक स्थिति है। एक ओर शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा संस्थानों पर 25 प्रतिशत प्रवेश क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहा है, वहीं वित्त मंत्रालय नए शिक्षण पदों के सृजन पर प्रतिबंध की अपेक्षा रखता है। वित्तीय संकट से जूझ रहे तमाम सरकारी विश्वविद्यालय जहां अपनी आवश्यकता से कम पदों पर नए शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, वहीं निजी संस्थान पूर्णकालिक शिक्षकों के बजाय अंशकालिक अध्यापकों को ही नौकरी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपेक्षाकृत कम वेतन देना होता है। न्यायालय का यह कहना कि शिक्षकों की वेतन संरचना को उनके कार्यों के आधार पर तर्कसंगत करना चाहिए, एक महत्वपूर्ण संदेश है।

आत्मघाती नींद से जगाने हेतु मानसूनी चेतावनी

राजेश निरुसंदेह, आपदा लाने वाले पैटर्न जलवायु परिवर्तन से जुड़े हैं जिसमें मानवीय गतिविधियां भी जिम्मेदार हैं। गलत नीतियों के चलते कंक्रीटीकरण, नदियों की राह पर अतिक्रमण व वन कटान जारी है। जिससे बाढ़, जनहानि व बुनियादी ढांचे को क्षति बढ़ रही है। इस विनाश पर अंकुश लगाने को नीतियों में जलवायु परिवर्तन चिंताओं को जगह, इफ्रास्ट्रक्चर के जलवायु अडिप्ट व पर्यावरणीय प्रभाव आकलन व्यवस्था की समीक्षा जरूरी है। दक्षिण-पश्चिम मानसून ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचा रखी है। अब तक मानसूनी बारिश सामान्य से अधिक रही है और चरम मौसम संबंधी अनेक घटनाएं देखने को मिली हैं। पहले पहाड़ी सूबे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व जम्मू और कश्मीर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए तो अब पंजाब में भी भारी बाढ़ की स्थिति बिगड़ती जा रही है, साथ ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाके भी प्रभावित हैं। दक्षिणी राज्यों के कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी भारी बारिश दर्ज की गई। बादल फटने, बाढ़, भूमि धंसने और भूस्खलन से जान-माल का काफी नुकसान हुआ है। इसी तरह, निजी संपत्ति और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भी भारी क्षति हुई। भारी बारिश के कारण पुल ढह गए हैं, कुछ बांध टूट गए, वहीं नए बने कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बह गए और जलविद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचने की सूचनाएं हैं। महत्वपूर्ण परिवहन संपर्क बाधित हुए हैं और फसलों की भारी तबाही की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी है कि यह सिलसिला अभी जारी रहेगा। सितंबर माह में भी देशभर में मासिक औसत वर्षा सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। जिससे बाढ़, भूस्खलन, सड़क परिवहन में व्यवधान, जन स्वास्थ्य चुनौतियां और पारिस्थितिक क्षति जैसी मुश्किलें पैदा होने जा रही हैं। यह वैज्ञानिक रूप से स्थापित है

कि वैश्विक मौसम बदलाव से भारतीय मानसून प्रभावित हुआ है। अध्ययन बताते हैं कि 1950 के दशक के बाद से अधिकांश थलीय क्षेत्रों में भारी वर्षा की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है, और इसकी एक बड़ी वजह मानव-जनित जलवायु बदलाव भी है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल (आईपीसीसी) द्वारा जारी आवृत्ति आकलन में इन निष्कर्षों का संश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। मौसम विज्ञान विशेषज्ञ मानसून की बड़ी तीव्रता के पीछे हिंद महासागर के ऊपर वायुमंडलीय नमी के अधिक जमाव को कारक मान रहे हैं, जो आगे, समुद्र सतह के तापमान में बढ़ोतरी के कारण बने अधिक वाष्पीकरण और साथ ही भूमि-समुद्र तापीय विषमता में इजाफे की वजह से यह जमाव ओर सघन हो रहा है। जैसे-जैसे मानसून विशालकाय वर्षा बादल समुद्र से लेकर, दक्षिण-पश्चिम



से पूर्व की ओर बढ़ता जाता है वायुमंडलीय नमी का बड़ा स्तर और ज्यादा नमी वाला आवरण पैदा करता जाता है, जिससे वृष्टि स्तर में और वृद्धि होती है। तो, क्या जो कुछ भी ओर रहा है उसके लिए हम आसान दोष जलवायु परिवर्तन पर मढ़ते जाएं और पर्यावरण, शहरी नियोजन, विकास, जल संसाधन, कृषि आदि से संबंधित अपनी सार्वजनिक नीतियों को पहले की भांति जारी रखें? बिलकुल नहीं। पहला, जलवायु परिवर्तन अपने आप में - जैसा कि आईपीसीसी द्वारा परिभाषित किया गया है - मानवीय गतिविधियों से पैदा घटना है। मसलन,

होती बहुत कम दिखाई देती है। राष्ट्रीय और राज्यों की जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाओं की प्रगति, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने तक ही सीमित होकर रह जाती है। दरअसल, सभी सार्वजनिक नीतियों में जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं को मुख्यधारा बनाए जाने की। मसलन, पहाड़ों में नए जलविद्युत संयंत्र, राजमार्ग या सुसंगत परियोजना का प्रस्ताव मंजूर करते वक्त अथवा निर्माण करते समय, हमें न केवल तात्कालिक पर्यावरणीय चिंताओं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न वर्तमान एवं भविष्य के जोखिमों का भी ध्यान रखना चाहिए।

विविध

ताकि देर तक चेहरा रहे ताजगी भरा



उमस, नमी और बारिश में मेकअप खराब हो सकता है। ऐसे में बेहतर समाधान है संपूर्ण चेहरे पर वॉटरप्रूफ मेकअप। लंबे समय तक मुँह पर ताजगी और चमक बनाए रखने के लिए मॉइश्चराइजर, आइशैडो आइलाइनर, मस्कारा और ब्लश के अलावा मेट बेस्ड लिपस्टिक अल्ट्राई करना चाहिए। बारिश का मौसम है और ऐसे में यदि आप कहीं घूमने या किसी पार्टी में जा रही हैं तो मेकअप में वॉटरप्रूफ मेकअप को ही अल्ट्राई करें। क्योंकि यदि आपने मेकअप बिना वॉटरप्रूफ कर लिया तो हो सकता है आपका मेकअप बरसात के कारण खराब हो जाए। यूं भी वॉटरप्रूफ मेकअप में एक से बढकर एक प्रोडक्ट आ रहे हैं जो आपके चेहरे को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जानिए, इस वॉटरप्रूफ मेकअप को आपको किस तरह करना चाहिए।

मेकअप बेस को बनाएं जब हम मेकअप करते हैं तो उसमें सबसे जरूरी यह तय करना होता है कि मेकअप का बेस किस तरह से बनाया जाए। मेकअप बेस जब सही तरह से बना होता है तो मेकअप का लुक ही अलग नजर आता है। मेकअप का बेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको चेहरे को ६

गोकर उसे अच्छी तरह से मॉइश्चराइज करना है। इसके बाद फाउंडेशन का इस्तेमाल करना है लेकिन फाउंडेशन क्रीम बेस्ड नहीं होना चाहिए। दरअसल, मानसून के मौसम में क्रीम बेस्ड फाउंडेशन लगाने से आपकी त्वचा चिपचिपी नजर आएगी। तो फाउंडेशन को पहले पुरे चेहरे पर लगा लें, इसके बाद मेट कॉम्पैक्ट लगाएं।

आंखों का मेकअप जब आपके चेहरे पर मेकअप का बेस बन जाए तो जरूरी है कि आप आंखों के मेकअप पर ध्यान दें। इसके लिए अपनी आंखों पर सबसे पहले आइशैडो लगाएं लेकिन आइशैडो वॉटरप्रूफ होना चाहिए। साथ ही ६ यान रखें कि बहुत ज्यादा भड़कीले आइशैडो का इस्तेमाल न करें। इसके बाद ही आपको वॉटरप्रूफ आइलाइनर और मस्कारा का इस्तेमाल करना है। यहां खास ख्याल रखने वाली बात ये है कि आपको क्रीम बेस्ड के बजाय पाउडर वाला आइशैडो का ही इस्तेमाल करना है।

ब्लश से करें हाइलाइट आंखों का मेकअप करने के बाद अगला चरण है, आपको अपनी चिकबोन पर ब्लश का इस्तेमाल करने का। इसके लिए आपको

मेकअप करते समय लाइट कलर में ब्लश को चिकबोन पर लगाना है। तो इसके लिए ब्लश को ब्रश की सहायता से चिकबोन पर लगाएं। लेकिन ध्यान दें कि पीच या फिर लाइट पिंक कलर में ही यह ब्लश होना चाहिए। साथ ही हाईलाइटर से नाक और चिकबोन को हाइलाइट करें। खास तौर पर इस तरह से मेकअप को हाईलाइट किया जाता है कि आपका मेकअप इससे उमरकर आता नजर आये। लेकिन इसका इस्तेमाल सही से करना जरूरी है। साथ ही अच्छी क्वालिटी के ही मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए।

लिपस्टिक जब पूरा मेकअप हो जाए तो सबसे लास्ट में बारी आती है लिप्स के मेकअप की। दरअसल लिपस्टिक हमारे मेकअप में सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब आप लिपस्टिक को लगाएं तो जरूरी है सबसे पहले कलर को देख लें कि आपके ऊपर सबसे ज्यादा कौन सा कलर सुंदर लग रहा है। इसके बाद ध्यान रखें कि आउकल वेदर मानसून का चल रहा है तो ऐसे में आपको क्रीम बेस्ड लिपस्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

क्या आप भी बार-बार करवाते हैं फेस क्लीन-अप तो हो जाइए सावधान

आजकल फेस क्लीन-अप स्किन केयर रूटीन का अहम हिस्सा बन गया है। कई लोग इसे हर महीने करवाते हैं ताकि चेहरा साफ और ग्लोइंग बना रहे। लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या सचमुच मासिक फेस क्लीन-अप सुरक्षित नहीं? चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब।

फेस क्लीन-अप क्या है? फेस क्लीन-अप एक स्किन ट्रीटमेंट है जिसमें चेहरे की गहराई तक सफाई की जाती है। इसमें क्लींजिंग, स्क्रबिंग, स्टीम, ब्लैकहेड/व्हाइटहेड रिमूवल और फेस पैक लगाया जाता है। यह फेशियल से हल्का और कम समय लेने वाला होता है।

मासिक फेस क्लीन-अप के फायदे गहराई से सफाई- इससे ६ लु, मिट्टी, पसीना और ऑयल के कारण जमी गंदगी हटती है। एक्ने और ब्लैकहेड्स में राहतक रूप से पोर्स साफ हो जाते हैं जिससे पिंपल्स कम होते हैं। ग्लोइंग स्किन- डेड स्किन सेल्स हटने से चेहरा चमकने लगता है।

खून का संचार बेहतर- मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और स्किन हेल्दी दिखती है।

कम खर्चीला- यह फेशियल से सस्ता और जल्दी हो जाने वाला प्रोसेस है।

किन बातों का ध्यान रखें? संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को हर महीने क्लीन-अप करने से जलन, लालिमा या एलर्जी हो सकती है। बार-बार स्क्रबिंग या स्टीम लेने से ड्रायनेस और इरीटेशन हो सकती है। अगर किसी को एक्टिव एक्ने, रैशेज या स्किन डिजीज है तो पहले डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें। क्लीन-अप हमेशा साफ-सुथरे और प्रोफेशनल सैलून/क्लिनिक में ही करवाएं।

किस कितनी बार करवाना चाहिए? ऑयली या नॉर्मल स्किन वालों के लिए महीने में एक बार क्लीन-अप करवाना फायदेमंद है। ड्राय या सेंसिटिव स्किन के लिए 6-8 हफ्तों में एक बार ही पर्याप्त है। पिंपल्स/एलर्जी प्रोन स्किन वाले डॉक्टर की सलाह पर ही क्लीन-अप करवाएं।



एमआरआई करवाते समय जरूर ध्यान रखें ये 5 बातें, वरना 1 मिनट में मशीन स्वीच सकती है अंदर



आजकल शरीर के अंदर की गंभीर बीमारियों जैसे ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, स्प्राइन की समस्या, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पता लगाने के लिए एमआरआई स्कैन एक बेहद जरूरी और कारगर तरीका है। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक एडवांस टेस्ट होता है जो शरीर के सॉफ्ट टिश्यूज की बेहद बारीक तस्वीरें दिखाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एमआरआई मशीन एक बहुत शक्तिशाली मैग्नेट (चुंबक) की 6-8 हफ्तों में एक बार ही पर्याप्त है। पिंपल्स/एलर्जी प्रोन स्किन वाले डॉक्टर की सलाह पर ही क्लीन-अप करवाएं।

अमेरिका में हुई थी गंभीर घटना एक घटना अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी, जिसमें 61 वर्षीय कीथ मैकएलिस्टर एमआरआई मशीन की वजह से गंभीर हादसे का शिकार हो गए। उनकी पत्नी का डल् स्कैन हो रहा था और जब उन्हें अंदर बुलाया गया, तो उनकी गर्दन में पहनी धातु की मोटी चेन की वजह से मशीन ने उन्हें खींच लिया।

वो करीब 1 घंटे तक मशीन में फंसे रहे और अगले दिन उनकी मौत हो गई। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, और इसलिए एमआरआई

कराते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। डल् से पहले जरूर करें ये 5 जरूरी काम...

धातु की कोई भी चीज साथ न ले जाएं

एमआरआई से पहले सबसे जरूरी है कि आप सभी मेटल की चीजें शरीर से हटा दें। इनमें गहने, चेन, चूड़ी, पियर्सिंग, बटन, घड़ी, बेल्ट, सिक्के, चाबी, पिन, हेयर क्लिप और यहां तक कि क्रेडिट ATM कार्ड भी शामिल हैं। एमआरआई मशीन एक बेहद ताकतवर मैग्नेट होती है जो किसी भी मेटल चीज को तेजी से खींच सकती है और यह जानलेवा साबित हो सकता है। बेहतर होगा कि ऐसी चीजें आप घर पर ही छोड़ दें।

अगर शरीर में कोई इमप्लांट हो, तो डॉक्टर को जरूर बताएं

अगर आपने शरीर में कोई इमप्लांट, जैसे कि पेसमेकर, कोकलियर इमप्लांट (कान का डिवाइस), धातु की प्लेट, सर्जिकल क्लिप, या आर्टिफिशियल जॉइंट लगाया है, तो डल् करवाने से पहले इसकी जानकारी डॉक्टर और टेक्नीशियन को दें। कुछ इमप्लांट्स एमआरआई मशीन के लिए सुरक्षित नहीं होते, और इससे खतरा हो सकता है।

कपड़ों का विशेष ध्यान रखें

अगर आपने स्पोर्ट्स ब्रा, वर्कआउट लेगिंग्स या एक्टिवियर पहना है, तो ध्यान दें कि इनमें कभी-कभी मेटालिक फाइबर होते हैं जो स्कैन के दौरान गर्म हो सकते हैं और जलन या चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए एमआरआई करवाने से पहले इस्पताल की तरफ से दिए गए स्पेशल गाउन पहनना ही बेहतर होता है।

स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी छुपाएं नहीं

एमआरआई से पहले अपने स्वास्थ्य की पूरी जानकारी डॉक्टर को जरूर दें। अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया (बंद जगह से डर) है, आप गर्भवती हैं, या आपको किडनी की बीमारी है, तो डॉक्टर को बताएं। डल् में इस्तेमाल होने वाली कुछ ड्राई या प्रक्रियाएं सभी लोगों के लिए सुरक्षित नहीं होती।

टेक्नीशियन की बात ध्यान से सुनें और मानें डल् के समय जो भी टेक्नीशियन मौजूद हो, उसकी हर बात ध्यान से सुनें और फॉलो करें। वो जो निर्देश देता है, वो आपकी सुरक्षा और बेहतर स्कैन रिजल्ट के लिए होता है। छोटी-छोटी बातों की अनदेखी भी बड़ी गलती साबित हो सकती है। एमआरआई स्कैन करवाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो...

उत्तर प्रदेश कांग्रेस आरटीआई विभाग के 5 वर्ष पूर्ण होने पर अभिनंदन समारोह आयोजित

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी एवं प्रदेश आरटीआई विभाग के चेयरमैन पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सूचना का अधिकार (आरटीआई) विभाग के 5 वर्ष पूर्ण होने पर अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि अजय राय ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि इस सफर में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने का उदाहरण करने का कार्य किया है, जिसके लिए सभी सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी देश के गरीब,



दलित, युवा, महिला, छात्र एवं किसानों के हितों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और पार्टी के सभी सदस्य उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। प्रदेश आरटीआई विभाग के चेयरमैन पुष्पेंद्र श्रीवास्तव ने भी उपस्थित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि विभाग की सफलता उनके सहयोग का

परिणाम है। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। श्रीवास्तव ने कहा कि आरटीआई कानून के माध्यम से मंडल स्तर पर आयोजित कार्यशालाओं एवं सूचनाओं के माध्यम से सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करना सराहनीय कार्य है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य

में भी यह काम निरंतर जारी रहेगा और सभी मंडलों में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने भाजपा पर भी तीखा हमला करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का लेखा-जोखा भगवान चित्रगुप्त के पास पहुँच चुका है और जनता उन्हें आगामी समय में सबक सिखाएगी। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता द्विजेंद्र त्रिपाठी, वीरेंद्र मदान, बुजेंद्र सिंह, विनोद मिश्रा, चंद्रशेखर मिश्रा, अंशु त्रिपाठी, डॉ. जियाराम वर्मा, अमित कुमार उदवाल, आशुतोष मिश्रा, विकास श्रीवास्तव सहित अन्य ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव और अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

जनता के साथ धोखा कर रही है पार्टी - अखिलेश यादव

लखनऊ, (संवाददाता)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित बैठक में भाजपा पर तीखा हमला

सकती है। उन्होंने भाजपा सरकार पर महंगाई बढ़ाने, बढ़ती बेरोजगारी और दोषपूर्ण जीएसटी के माध्यम से जनता को लूटने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि गरीब, किसान



करते हुए कहा कि यह पार्टी जनता को पिछले एक दशक से धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्षी दलों और मतदाताओं के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करती है और अपनों को भी धोखा देने से पीछे नहीं हटती। अखिलेश यादव ने कहा कि केवल भाजपा हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अन्याय, अत्याचार और गैरबराबरी समाप्त हो

और मध्यम वर्ग को भाजपा की नीतियों से भारी नुकसान हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को ईमानदार होना चाहिए और जनता के प्रति भाषा एवं व्यवहार उचित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) की बढ़ती ताकत से भाजपा भयभीत है और जनता इसे सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव ने पर्यावरण के

लिए भाजपा सरकार की विफलताओं को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि नदियों की सफाई नहीं हुई, पेड़ काटे गये और पहाड़ी राज्यों में अनियोजित कार्यों से भारी तबाही हुई है। उन्होंने हिमालय बचाओ अभियान का उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जनधन और पशुधन की भारी हानि हुई है। उन्होंने भाजपा सरकार पर झूठे दावे करने और अर्थव्यवस्था को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी नीतियों पर ही गैरबराबरी को दूर किया जा सकता है। उन्होंने समाजवादी सरकार के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों जैसे छात्रों को लेपटॉप वितरण, एक्सप्रेस-वे, आईटी सिटी, स्टेडियम, पार्क, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और स्कूल निर्माण, किसानों को सुविधाएँ और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने का उदाहरण दिया।

जीएसटी काउंसिल के फैसलों से जनता को तुरंत राहत नहीं - अमरनाथ मिश्र

लखनऊ, (संवाददाता)। व्यापारी नेता अमरनाथ मिश्र ने जीएसटी काउंसिल के हालिया फैसलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये फैसले देखने में भले ही उत्साहवर्धक लग रहे हों, लेकिन आम जनता को तत्काल कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कई बिंदुओं पर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है, जिसके चलते व्यापारी वर्ग और उपभोक्ता दोनों असमंजस में हैं। मिश्र ने कहा कि मानव निर्मित धागों पर 5 प्रतिशत जीएसटी तय किया गया है, लेकिन इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) अनुमत्य नहीं है। वहीं एंक्रैलिक और नाइलॉन धागों पर और माना जा रहा है कि इन पर अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जनधन और पशुधन की भारी हानि हुई है। उन्होंने भाजपा सरकार पर झूठे दावे करने और अर्थव्यवस्था को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी नीतियों पर ही गैरबराबरी को दूर किया जा सकता है। उन्होंने समाजवादी सरकार के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों जैसे छात्रों को लेपटॉप वितरण, एक्सप्रेस-वे, आईटी सिटी, स्टेडियम, पार्क, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और स्कूल निर्माण, किसानों को सुविधाएँ और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने का उदाहरण दिया।

लखनऊ, (संवाददाता)। व्यापारी नेता अमरनाथ मिश्र ने जीएसटी काउंसिल के हालिया फैसलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये फैसले देखने में भले ही उत्साहवर्धक लग रहे हों, लेकिन आम जनता को तत्काल कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कई बिंदुओं पर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है, जिसके चलते व्यापारी वर्ग और उपभोक्ता दोनों असमंजस में हैं। मिश्र ने कहा कि मानव निर्मित धागों पर 5 प्रतिशत जीएसटी तय किया गया है, लेकिन इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) अनुमत्य नहीं है। वहीं एंक्रैलिक और नाइलॉन धागों पर और माना जा रहा है कि इन पर अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जनधन और पशुधन की भारी हानि हुई है। उन्होंने भाजपा सरकार पर झूठे दावे करने और अर्थव्यवस्था को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी नीतियों पर ही गैरबराबरी को दूर किया जा सकता है। उन्होंने समाजवादी सरकार के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों जैसे छात्रों को लेपटॉप वितरण, एक्सप्रेस-वे, आईटी सिटी, स्टेडियम, पार्क, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और स्कूल निर्माण, किसानों को सुविधाएँ और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने का उदाहरण दिया।

लखनऊ, (संवाददाता)। व्यापारी नेता अमरनाथ मिश्र ने जीएसटी काउंसिल के हालिया फैसलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये फैसले देखने में भले ही उत्साहवर्धक लग रहे हों, लेकिन आम जनता को तत्काल कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कई बिंदुओं पर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है, जिसके चलते व्यापारी वर्ग और उपभोक्ता दोनों असमंजस में हैं। मिश्र ने कहा कि मानव निर्मित धागों पर 5 प्रतिशत जीएसटी तय किया गया है, लेकिन इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) अनुमत्य नहीं है। वहीं एंक्रैलिक और नाइलॉन धागों पर और माना जा रहा है कि इन पर अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जनधन और पशुधन की भारी हानि हुई है। उन्होंने भाजपा सरकार पर झूठे दावे करने और अर्थव्यवस्था को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी नीतियों पर ही गैरबराबरी को दूर किया जा सकता है। उन्होंने समाजवादी सरकार के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों जैसे छात्रों को लेपटॉप वितरण, एक्सप्रेस-वे, आईटी सिटी, स्टेडियम, पार्क, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और स्कूल निर्माण, किसानों को सुविधाएँ और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने का उदाहरण दिया।

संक्षिप्त स्वबरें

लखीमपुर खीरी में होगा दुधवा महोत्सव-2025, पर्यटन और वन्यजीव प्रेमियों के लिए अनोखा अनुभव

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार राज्य वन क्षेत्र में दुधवा महोत्सव-2025 आयोजित करने जा रही है। पर्यटन विभाग के अनुसार यह महोत्सव नवंबर माह में लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में होगा। यह आयोजन आवासीय, सांस्कृतिक और वन्यजीव आधारित गतिविधियों का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि महोत्सव में देश-विदेश से पर्यटक शामिल होंगे, जिससे प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में पहचान मिलेगी। तीन दिवसीय कार्यक्रम में पर्यटक वन क्षेत्र की सुंदरता का आनंद लेने के साथ-साथ थारु जनजाति की संस्कृति, खानपान, हस्तशिल्प और जीवनशैली का अनुभव भी कर सकेंगे। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि महोत्सव की थीम ईको-टूरिज्म, नेचर एंड कल्चर सेलिब्रेशन होगी। उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इस महोत्सव के लिए व्यापक कार्ययोजना पर काम कर रहा है। दुधवा महोत्सव प्रकृति प्रेमियों, परिवारों, कलाकारों, विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वन्यजीव सफारी, गाइडेड टूर और जैव विविधता का समग्र अनुभव प्रदान करेगा। नदेशक यूपी टूरिज्म (इको) प्रखर मिश्रा ने कहा कि यह महोत्सव प्रदेश के वन्यजीव और जैव विविधता को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण अवसर है। आगंतुकों को इको-फ्रेंडली कैम्पिंग, जंगल सफारी, लोक कला प्रस्तुतियाँ और स्थानीय जीवनशैली का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। इसके लिए पर्यटन सुविधाओं का विस्तार और स्थानीय समुदाय की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस महोत्सव से दुधवा में इको-पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद है, जिससे राज्य का पर्यटन क्षेत्र और अधिक सशक्त और आकर्षक बनेगा।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का चार दिवसीय भ्रमण जनता की समस्याओं की सुनवाई और पर्यटन परियोजनाओं का शिलान्यास

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह कल से चार दिवसीय भ्रमण पर रहेंगे, जिसमें वे उन्नाव, फिरोजाबाद, मैनपुरी और फर्रुखाबाद का दौरा करेंगे। भ्रमण के कार्यक्रम के अनुसार, कल अपराह्न 03 बजे अरोड़ा रिसॉर्ट, उन्नाव में स्व0 अजीत सिंह जी की 31वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि समा में वे शामिल होंगे। इसके बाद 06 सितंबर को सुबह 09 बजे से दोपहर 01 बजे तक ट्रांजिट हॉस्टल, पीडब्ल्यूडी पुलिस लाइन में आम जनता की समस्याओं की सुनवाई करेंगे। इसी दिन मंत्री घंटाघर मैनपुरी में पर्यटन विकास से संबंधित थीमेटिक गेट सहित अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 07 सितंबर, रविवार को वे कैम्प कार्यालय, सिरसागंज, फिरोजाबाद में जनता की समस्याएं सुनेंगे। इसके बाद ठाकुर जी महाराज मंदिर प्रांगण, शिकोहाबाद में पर्यटन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अगले दिन, निरीक्षण भवन, फर्रुखाबाद में लोगों से मुलाकात करेंगे और दोपहर 12 से 01 बजे तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके पश्चात कलेक्ट्रेट सभागार, फर्रुखाबाद में जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और सायं 06 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे।

संक्षिप्त स्वबरें

सज गया किताबों का संसार

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी के बलरामपुर गार्डन में दस दिवसीय 22वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का बृहस्पतिवार को आगाज हो गया। इसका उद्घाटन राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने किया। आयोजकों ने राज्यपाल को पुस्तकें और पौधे भेंट किए। पुस्तक मेले में सभी उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ है। यहां बच्चों के साहित्य का संसार भी सजा हुआ है। ओशो फाउंडेशन और फिर डॉ. शशि चक्रवर्ती और साधियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। मौके पर मनोज सिंह चंदेल, सह संयोजक आस्था ढल, आकर्षण जैन, मेला निदेशक आकर्ष चंदेल, टीपी हवेलिया व ज्योति किरन रतन आदि मौजूद रहे। एक इंच की गीता बनी आकर्षण का केंद्र : मेले में अहमदाबाद के प्रकाशक अपूर्ण शाह की एक इंच की गीता और ताम्रपत्र पर लिखी हनुमान चालीसा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अपूर्ण ने राज्यपाल को यह सूक्ष्म गीता गुटका भेंट की। अपूर्ण की पत्नी क्षमा शाह भी मौजूद रहीं। नवरंग प्रकाशन की स्टॉल पर यह बिक्री के लिए उपलब्ध है।

ई कॉमर्स व स्टिल ट्रेड पॉलिसी बनाए सरकार

लखनऊ, (संवाददाता)। जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की ओर से अयोध्या रोड स्थित प्रदेश कार्यालय में परिचर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि 5 व 18 प्रतिशत के स्लैब से जनता की जेब पर खर्च का बोझ कम पड़ेगा। उन्होंने सरकार से ई कॉमर्स पॉलिसी एवं रिटेल ट्रेड पॉलिसी की ओर अगला कदम रखने की मांग की। ताकि देश के परंपरागत व्यापारी बच सकें। जीएसटी सरलीकरण, पेंट उद्योग को 18 से 5 प्रतिशत दर में लाने, फर्नीचर पर जीएसटी कम करने की मांग उठी। नगर अध्यक्ष हरजिंदर सिंह, ट्रांस गोमती प्रभाषी मनीष पांडेय, ट्रांस गोमती अध्यक्ष अनिरुद्ध निगम, प्रदेश उपाध्यक्ष इकबाल हसन, शेखर कुमार, नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमिताभ श्रीवास्तव, सर्वेश मिश्रा, महिला इकाई की वरिष्ठ उपाध्यक्ष वर्तिका शुक्ला मौजूद रहीं।

लखनऊ में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

लखनऊ, (संवाददाता)। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मोर्य के नेतृत्व एवं निर्देशन में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ में विभिन्न सरकारी और अर्धसरकारी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य प्रतिभागियों को और अधिक दक्ष, सक्षम और कर्मयोगी बनाना है। संस्थान के महानिदेशक एल0 वेंकटेश्वर लू के संरक्षण एवं प्र0 अरुण निदेशक सुबोध दीक्षित के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में वैश्वीय प्रबंधन एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन, ई-ऑफिस, ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल, मानव सम्पदा पोर्टल, जेम पोर्टल, कृषि उत्पादक संगठनों एवं महिला कृषक संघों का क्षमता संवर्धन शामिल थे। इसके अलावा, केन्द्रीय सचिवालय प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली द्वारा सहायक अनुभाग अधिकारियों के लिए विलेज अटैचमेंट है।

ध्वजारोहण समारोह से पहले बदलेगी राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था, बैठक में हुए कई अहम निर्णय

लखनऊ, (संवाददाता)। भव्य राम मंदिर में आगामी ध्वजारोहण समारोह को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था



और अधिक कड़ी की जा रही है। श्रीराम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिनके आधार पर मंदिर परिसर की सुरक्षा रूपरेखा में व्यापक बदलाव

किए जाएंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले परिसर में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई जाएगी और आधुनिक

जाएगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि नवंबर से राम मंदिर परिसर स्थित अन्य प्राचीन मंदिरों को भी आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। इससे आने वाले पर्यटकों और भक्तों को अयोध्या की धार्मिक धरोहर का अधिक सजीव अनुभव मिलेगा। रामलला के दर्शन को आए दिन लाखों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा प्रबंधन और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन में सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही सुरक्षा कवच भी और मजबूत होगा। परिसर को आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस करने के कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। आईजी परिक्षेत्र प्रवीण कुमार ने बताया कि परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन किया गया है।

लखनऊ, (संवाददाता)। राम मंदिर से पांच सितंबर को इतिहास का नया अध्याय जुड़ गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पहले विदेशी प्रधानमंत्री के रूप में भूटान के पीएम दासो शेरिंग टोबगो ने अपनी धर्मपत्नी के साथ रामलला के दर्शन किए। भूटान के प्रधानमंत्री शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे अपने तय कार्यक्रम के अनुसार भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से बिहार के गया से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधि के रूप में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही

रामलला के किए दर्शन, करीब दो घंटे राम जन्मभूमि परिसर में बिताए

लखनऊ, (संवाददाता)। राम मंदिर से पांच सितंबर को इतिहास का नया अध्याय जुड़ गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पहले विदेशी प्रधानमंत्री के रूप में भूटान के पीएम दासो शेरिंग टोबगो ने अपनी धर्मपत्नी के साथ रामलला के दर्शन किए। भूटान के प्रधानमंत्री शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे अपने तय कार्यक्रम के अनुसार भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से बिहार के गया से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधि के रूप में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही



समेत विदेश मंत्रालय, शासन, प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। यहां से प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से सीधे राम मंदिर के लिए रवाना हुए। इस दौरान थोड़ी देर के लिए हाईवे पर यातायात

प्रतिबंधित कर दिया गया। भूटान के पीएम सुबह 10:00 बजे राम मंदिर पहुंचे। करीब एक घंटे 40 मिनट के राम मंदिर प्रवास में उन्होंने रामलला और राम दरबार के दर्शन किए। इसके साथ ही कुबेर टीला, जटायु और सप्त मंडपम के मंदिरों में भी दर्शन पूजन किया। उन्होंने लोअर प्लिथ के चारों ओर लगने वाले म्यूरल के साथ परकोटा की दीवार पर लगने वाले ब्रांज के म्यूरल को भी निहारा। इस दौरान अपने मोबाइल से रामजन्मभूमि परिसर की तस्वीरें कैद करते रहे। राम मंदिर की नक्काशी उनको बहुत अच्छी लगी। राम मंदिर में दर्शन और भ्रमण के दौरान वह काफी प्रसन्न थे। रामलला के दरबार में उन्होंने तीन बार साष्टांग प्रणाम किया। रामलला की आरती उतारी और पुष्प अर्पित किया। इसके बाद चरणामृत प्रसाद ग्रहण किया। राम मंदिर से प्रधानमंत्री होटल रामायण पहुंचे। यहां पर भूटान की पारंपरिक शैली में सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उनका स्वागत किया गया। प्रदेश सरकार की पहल पर जिला प्रशासन की ओर से उनके सम्मान में दोपहर भोज का आयोजन किया गया। दोपहर भोज में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री अयोध्या एयरपोर्ट आए और यहां से भारतीय वायुसेना के विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले में पुलिस पर गिरी गाज, दसोगा सहित चार सस्पेंड

लखनऊ, (संवाददाता)। बाराबंकी स्थित श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के बाहर बिना मान्यता एलएलबी कोर्स संचालित करने का विरोध करने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करने वाले चौकी इंचार्ज, दो मुख्य आरक्षी और एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। इस प्रकरण की जांच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आईजी रंज अयोध्या प्रवीण कुमार को सौंपी थी, जिन्होंने अपनी अंतरिम रिपोर्ट बुधवार रात डीजीपी राजीव कृष्ण को सौंप दी। आईजी की संस्तुति पर एसपी बाराबंकी ने दोषी पाए पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक आईजी रंज को लाठीचार्ज की घटना की वीडियो फुटेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर बेरहमी

से लाठियां बरसाने वाले चौकी इंचार्ज गजेंद्र विक्रम सिंह, मुख्य आरक्षी पवन यादव, सौरभ सिंह और सिपाही विनोद यादव को दोषी पाते हुए निलंबित करने की संस्तुति की थी। अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में सीओ सिटी हर्षित चौहान और इंस्पेक्टर बाराबंकी कोतवाली आरके राणा की भूमिका की जांच की जा रही है। जांच पूरी करने के बाद आईजी रंज अंतिम रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपेंगे। बता दें कि घटना के बाद मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए सीओ को हटाने का आदेश दिया था, जबकि इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया था। वहीं विश्वविद्यालय द्वारा बिना मान्यता एलएलबी कोर्स संचालित करने के प्रकरण की जांच मेंडलायुक्त अयोध्या को सौंपी गई थी। बता दें कि बुधवार देर रात मेंडलायुक्त और आईजी रंज अयोध्या की जांच रिपोर्ट के बाद



विश्वविद्यालय के खिलाफ बाराबंकी कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। इस मामले में छात्रों का कहना है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर केवल फैंकटैली व स्टाफ की आवाजाही रोकी थी, छात्राओं को थोड़ा रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। सीओ सिटी हर्षित चौहान मौके पर पहुंचे, लेकिन मान्यता से जुड़े सवाल

पर जब उनके पास संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। इसी खींचतान के बीच अचानक लगभग 4:00 बजे यूनिवर्सिटी गेट के अंदर से कुछ लोग बाहर आए। उन्होंने गेट के डंडे खींचकर छात्रों पर हमला बोल दिया। कुल 21 मिनट के इस घटनाक्रम में कौन-कौन लोग शामिल रहे, किसने

हमला किया और किसने भड़काने की साजिश रची यह बड़ा सवाल है। लाठीचार्ज मामले में अब तक सीओ, कोतवाली, चौकी इंचार्ज व एक सिपाही को हटाया गया है। जांच के दौरान ओर सिपाहियों को चिह्नित किया गया है। दोनों की जांच कराई जा रही है। दोषी मिलने पर कार्रवाई होगी।

भारत की 11 बेटियों को मिलेगा सर्वाधिक ऊँचाई वाले पर्वतारोहण का प्रशिक्षण

लखनऊ। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली के प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 'नीव' से शिखर तक के दूसरे बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस समारोह

फिट इंडिया मूवमेंट के निदेशक नदीम भी उपस्थित थे। इस अवसर पर, एम3एम फाउंडेशन की चेरपरसन एवं ट्रस्टी डॉ. पायल कनोडिया ने अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए बताया कि, "नीव से शिखर तक



में एम3एम फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी एवं अध्यक्ष डॉ. ऐश्वर्य महाजनय भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के उप महानिदेशक मयंक श्रीवास्तव, आईपीएसय और

एक पर्वतारोहण पहल से कहीं बढ़कर है यह एक नेतृत्व यात्रा है जो जमीनी स्तर से शुरू होकर महानता की ओर बढ़ती है। ये युवा लड़कियां न केवल चोटियों पर चढ़ रही हैं वे बाधाओं

को तोड़ रही हैं और जो संभव है उसे फिर से लिख रही हैं। बैच 2 के साथ, हमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की महत्वाकांक्षी बेटियों को यह अवसर प्रदान करने पर गर्व है। हमारा मिशन यह सुनिश्चित करना है कि सपने देखने वाली हर लड़की को शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए उपकरण, प्रशिक्षण और आत्मविश्वास दिया जाए।" बैच 2 में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा की 11 वंचित लड़कियों का एक नया समूह अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान, मनाली में एक निःशुल्क बुनियादी पर्वतारोहण पाठ्यक्रम से गुजरेंगे। भारत की फिट इंडिया एम्बेसडर के मार्गदर्शन में, लड़कियों को रॉक क्राफ्ट (चढ़ाई, रैपिडिंग, जुमारिंग), स्नो और आइस क्राफ्ट (सीढ़ियों काटना, आइस एक्स अरेस्ट, क्रैम्पन

का उपयोग), रस्सी का काम (गॉट बनाना, लंगर डालना, नदी पार करना) और जीवन रक्षा कौशल (तंबू लगाना, आश्रय बनाना, ऊँचाई पर रहना) का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तकनीकी प्रशिक्षण के साथ-साथ, उन्हें नेतृत्व विकास सत्रों में भी शामिल किया जाएगा, जो टीम वर्क, अनुशासन और लचीलेपन पर जोर देते हुए उन्हें न केवल पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, बल्कि आत्मविश्वास और शक्ति के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करेंगे। यह पहल बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की भावना से गहराई से जुड़ी हुई है, जिसका उद्देश्य किशोर लड़कियों को संरचित शारीरिक चुनौतियों, मार्गदर्शन और जीवन कौशल से सशक्त बनाना है। बैच 2 का शुभारंभ कुरुक्षेत्र में बैच 1 के सफल शुभारंभ के बाद हुआ है।

खेत में चारा काटने गए व्यक्ति की बाढ़ के पानी में डूबने से हुई मौत

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना)

शाहाबाद तहसील क्षेत्र में बाढ़ का पानी अब जानलेवा साबित हो रहा है। शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के कालागाढ़ा गाँव में शनिवार को गाँव के पास ही खेत पर चारा काटने गए एक व्यक्ति की बाढ़ के पानी में डूबकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक सुनील कुमार (42) पुत्र रामचन्द्र रोजाना की तरह घर से खेत पर चारा काटने गए थे। इसी दौरान अचानक



बाढ़ के पानी में गहराई में चले जाने से वह डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही गाँव के लोग मौके पर पहुँचे और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुनील को बाहर निकाला। आनन-फानन में परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुँचे, जहाँ डॉक्टरों ने जांच के बाद सुनील को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सुचना मिलते ही शाहाबाद ब्लॉक प्रमुख त्रिपुरेश मिश्रा व जिलापंचायत सदस्य लालाराम राजपूत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहाबाद पहुंचे, उन्होंने परिजनों का ढांडस बंधाया व हर सम्भव मदद का भरोसा दिया। वहीं बाढ़ के पानी में डूबकर 42 वर्षीय सुनील की बाढ़ में डूबने से मौत होने के बाद गाँववालों ने प्रशासन से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षा के इंतजाम और राहत कार्यों को तेज करने की मांग की है।

सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों ने पैदल मार्च किया

सिटी रिपोर्टर प्रत्युष पाण्डेय

लखनऊ। बाराघाट के जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए चप्पे चप्पे पर चीफ वार्डेन अमरनाथ मिश्रा के नेतृत्व में अमीनाबाद से रकाबागंज, यहियागंज, नक्खास चौराहा, दूरियागंज, हैदरगंज चौराहा से पीली कालोनी होते हुए ऐशबाग ईदगाह तक पैदल मार्च किया। जुलूस में मुख्य रूप से डिप्टी चीफ वार्डेन गुरप्रीत सिंह सेटी, स्टॉफ ऑफिसर टू चीफ वार्डेन ऋतुराज रस्तोगी, डिविजनल वार्डेन सुनील कुमार शुक्ला, नफीस अहमद, आशीष कपूर, हरीश चन्द्र, दिनेश माथुर, सतेंद्र शर्मा, डिप्टी डिविजनल वार्डेन मुशीर अहमद, रामगोपाल सिंह, सुनील कुमार कर्मचंदानी, राजेन्द्र कुमार वर्मा, रियाजउद्दीन, रीता पटेल, मजीद अली, राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रदीप शर्मा, सुमित साहू, ऐश्वर्य शर्मा, आलोक सक्सेना, अनंत तोमर आदि सैकड़ों वार्डेन उपस्थित रहे।



पीलीभीत, रकाबागंज, यहियागंज सिद्धनाथ मंदिर, वर्मा स्टॉप, नक्खास चौराहा, बिलोजपुरा, दूरियागंज, हैदरगंज चौराहा और ऐशबाग ईदगाह पर सिविल डिफेंस के कैम्प भी लगाए गए।

'तहसीलदार सवायजपुर ने बाढ़ प्रभावित गांवों का किया दौरा'



'रिपोर्ट-जनार्दन श्रीवास्तव' पाली-(हरदोई) गर्ग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण बाढ़ का पानी क्षेत्र के कई गांवों में घुस गया है। बाढ़ प्रभावित गांवों में आवागमन भी प्रभावित हुआ है। वहीं बाबरपुर गांव बाढ़ की चपेट में है। ग्राम प्रधान किशन राम मिश्रा ने बताया कि बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है। उन्होंने बताया कि सुशील कुमार पुत्र महेंद्र नाथ एवं मुन्नी देवी पत्नी स्व० राजेन्द्र प्रसाद का मकान बाढ़ की चपेट में आकर नदी में समा गया, जिससे नदी के किनारे बसे ग्रामीणों ने

अपने मकान स्वयं तोड़ने शुरू कर दिए हैं। ग्राम प्रधान ने बताया कि बाढ़ प्रभावित लोगों के रहने एवं भोजन आदि की व्यवस्था उनके द्वारा बगीचे में कैम्प लगाकर मुहैया कराई जा रही है। साथ ही कटान वाले स्थानों पर मिट्टी से भरी बेरियां लगाकर कटान को रोकने का प्रयास जारी है। एक-दो मकानों के गर्ग नदी में समा जाने से ग्रामीण डरे और सहमें हुए हैं। सवायजपुर तहसीलदार विनोद कुमार एवं बीडीओ भरखनी अशोक द्विवेदी शनिवार को बाबरपुर गांव पहुंचे और यहां उन्होंने बाढ़ की स्थिति का

जायजा लिया तथा ग्रामीणों को मदद का भरोसा दिलाया। वहीं बीते शुक्रवार को बाबरपुर गांव में जिलाधिकारी अनुनय झा एवं पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन पहुंचे थे और नदी के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण कर ग्रामीणों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था। शुक्रवार-शनिवार की मध्य रात्रि में गर्ग नदी में अत्यधिक जल वृद्धि हुई जिससे नदी का पानी बाबरपुर एवं कहारकोला गांव के अंदर घुस गया है। कहारकोला गांव जाने वाले रास्ते पर पानी भरने से आवागमन ठप्प हो गया है। ग्राम बाबरपुर में नदी किनारे के मकानों में कटान शुरू हो गया है, यहां के एक-दो मकान और कई पेड़ नदी में समा चुके हैं। नदी के किनारे पर बसे ग्रामीणों ने अब अपने मकान स्वयं तोड़ने शुरू कर दिए हैं, उनका कहना है कि कम से कम ईंटें तो बच ही जाएंगी अन्यथा नदी के कटान से कुछ भी बचना मुश्किल है। तहसीलदार सवायजपुर विनोद कुमार एवं खंड विकास अधिकारी है।

सांक्षिप्त खबरें

'जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा'

'रिपोर्ट-जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' शुक्रवार को जिलाधिकारी अनुनय झा व पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने पाली क्षेत्र के अन्तर्गत बाबरपुर में बाढ़ का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावितों से संवाद किया तथा प्रशासन द्वारा दी जा रही सहायता के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मेडिकल कैंप व पशुपालन विभाग द्वारा लगाए गए कैंप को भी देखा तथा स्पष्ट निर्देश



दिये कि क्षेत्र में बीमार लोगों को दवा का वितरण किया जाए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को उन्होंने निर्देशित किया कि पशुओं के स्वास्थ्य की जांच कर ली जाए तथा बीमार पशुओं को दवा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने लोगों से कहा कि प्रभावित क्षेत्र के लोग बाढ़ शरणालय में चले जाएं। उनके द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत किट व फूड पैकेट भी वितरित किए गए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन घरों में खाना पकाना संभव न हो, उनको पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाए। जरूरतमंदों को राशन किट उपलब्ध कराई जाए। निजी पशुओं के रहने के लिए भी शरणालय की एक व्यवस्था बनाई जाए। लोगों को क्लोरीन की गोलियां दी जाये तथा क्षेत्र में फागिंग कराया जाये। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रफुल्ल त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी मयंक कुंडू, नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिवेदी, प्रभारी जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

'महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रति किया जागरूक'

'रिपोर्ट-जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित संकल्प हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमन के अन्तर्गत सितंबर माह में 10 दिवसीय विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधि कार्यक्रम यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम शुक्रवार को जनपद हरदोई के 100 शैत्या अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया व गर्भवती महिलाओं को पोषित आहार की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में वन स्टॉप से मिथलेश वर्मा, सुरभि सिंह हब फॉर इंपावरमेंट से पल्लवी मिश्रा मौजूद रहे।

पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष.. तलवारें खिंची, 12 से अधिक लोग घायल



पीलीभीत, (संवाददाता)। पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र के गांव बाकरगंज में बृहस्पतिवार रात को पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ओर से लाठी-डंडे, बांके और तलवारें चलीं, जिससे 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहानाबाद लाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला

अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जहानाबाद क्षेत्र के गांव बाकरगंज निवासी बलीशेर और सलीम पक्ष के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही है। दोनों ओर से मुकदमेशुकी हो चुकी है। कुछ लोग जेल भी जा चुके हैं। पुलिस ने कई बार दोनों पक्षों पर 107६ की कार्रवाई की थी, इसके बावजूद विवाद नहीं थमा। बताया जाता है कि बृहस्पतिवार को धरलू बातचीत का वीडियो बनाए जाने

को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि सलीम पक्ष द्वारा गाली-गलौज की गई, जिससे मामला तूल पकड़ गया और बाकरगंज मस्जिद के पास दोनों गुट भिड़ गए। जमकर मारपीट हुई। लाठी-डंडे और बांके चले। तलवारें खिंच गईं, जिससे गांव में दहशत फैल गई। संघर्ष के दौरान गोली चलने की भी चर्चा रही, लेकिन पुलिस ने फायरिंग से इनकार किया है। थाना प्रभारी प्रदीप विश्वा ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

घायलों में बलीशेर पक्ष से छोटे शाह, ताहिर, शराफत, दिलशाद, रिहान, जीशान और खातून शामिल हैं। वहीं सलीम पक्ष से मेराज, तस्लीम, रिजवान, जहीर, सना और इम्तियाज घायल हुए हैं। दोनों ओर से छह-छह अन्य लोगों के खिलाफ भी नामजदगी की गई है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

बाढ़ के पानी में डूबकर मासूम की मौत, मुश्किल में जिंदगी

सीतापुर, (संवाददाता)। सरयू और शारदा नदियों में उफान से तटवर्ती इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। रामपुर मथुरा में घर के बाहर गड्ढे में भरे बाढ़ के पानी में डूबकर तीन साल के मासूम की मौत हो गई। सरयू में कटकर एक घर बह गया। 10 मकान लहरों के निशाने पर हैं। लहरपुर, महमूदाबाद व बिसवां तहसील क्षेत्रों के 70 से ज्यादा गांवों के 150 घरों में बाढ़ का पानी भर गया है। लगभग 65 हजार आबादी प्रभावित है। घरों में पानी भरने से लोगों के सामने रहने और खाने का संकट खड़ा हो गया है। सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए ग्रामीण नाव का सहारा ले रहे हैं। सैकड़ों बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रामपुर मथुरा में बाबाकुटी निवासी प्रेम गौतम का बेटा शिवांक (3)

बृहस्पतिवार को घर के बाहर खेल रहा था। घर के पास बने एक गड्ढे में भरे बाढ़ के पानी में वह गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि शिवांक के पिता प्रेम जयपुर में नौकरी करते हैं। तहरीर मिलने पर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। शुक्रपुर के प्रधान श्रीराम ने बताया कि सुंदरपुरवा निवासी बेनीराम का घर कटकर बह गया है। इसी गांव के विशंभर के घर का अधिकांश हिस्सा भी नदी में कट चुका है। ब्रजेश व कालिया ने बताया कि उनके घर कटान की जद में हैं। लोधनपुरवा निवासी कुंवारे ने बताया कि उनका और बहादुर, मौजीलाल, संतराम, जगन्नाथ, श्रीपाल व बालक के घर लहरों के निशाने पर हैं। नदी की धारा इन घरों से महज पांच मीटर दूर है। बहादुर ने बताया कि बाढ़ की आहत होते ही बिजली काट दी गई है। इससे रात में अंधेरा

पसरा रहता है। मौजी ने बताया कि खेत जलमग्न हैं, यदि ज्यादा दिन पानी भरा रहा तो फसलें सड़ जाएंगी। रामसमुझ ने बताया कि नागेश्वरपुरवा, सुंदरपुरवा, लोधनपुरवा, बचकपुरवा, अर्जुनपुरवा, सौतीपुरवा, गोमतीपुरवा, बलेशपुरवा, निरंजनपुरवा, बाबाकुटी व प्यारपुरवा सहित 50 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इन गांवों के करीब 100 घरों में पानी भर गया है। इससे लोग गृहस्थी समेटकर तटबंध पर शरण लेने को मजबूर हैं। महमूदाबाद तहसीलदार अनिल कुमार ने बताया कि कटान का सर्वे कराया जा रहा है। पीड़ितों को राशन किट, तिरपाक के अलावा 90 टर्च वितरित की गई हैं। शारदा का रौद्र रूप तराई इलाके में दिख रहा है। भदफर, रमुवापुर, चंदवासोत, मंझरी पासिन मंझरी, कारिदा, घोसियाण, टिकौना, तेजपुर, बेलवा डिंगरा, पट्टी देहली, रमुपुरवा बेलवापुरा, रतौली सोसरी, मुशियाणा,

कड़ी सुरक्षा के बीच आज से शुरू हुई दो दिवसीय पीईटी परीक्षा

अयोध्या।कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यूपी पीईटी परीक्षा जिले के 30 केंद्रों पर 6 सितंबर को दो पाली में संपन्न हुई। 6 सितंबर को आयोजित प्रथम पाली परीक्षा में कुल मिलाकर 12576 अभ्यर्थियों में से 10404 कुल अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल रहे। वहीं

2172 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। जबकि दूसरे पाली में 12576 अभ्यर्थियों में से कुल 10396 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल रहे। वहीं 2180 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे।। प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के अलावा एक-एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति द्वार के निर्माण कार्य का राज्य मंत्री ने किया शिलान्यास

ब्यूरो प्रमुख विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जौनपुर। शनिवार को खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चन्द्र यादव जी हरदीपुर गांव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० बाबा रुखडदास पाण्डेय, स्व० शिवप्रसाद पाण्डेय, स्व० त्रिभुवन नाथ पाण्डेय, स्व० शिवदत्त पाण्डेय, स्व० रघुनाथ यादव, स्व० जनार्दन प्रसाद पाण्डेय व स्व० मोहन पाण्डेय जी के सम्मान में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत प्स्वतंत्रता



संग्राम सेनानी स्मृति द्वार के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसी क्रम में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चर्चटिया, सूरजघाट रोड पर राजकुमार राय के मकान से अंजू देवी के मकान तक विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि

योजना के अंतर्गत बने इंटरलॉकिंग रोड का लोकार्पण किया। इस अवसर क्रम में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चर्चटिया, सूरजघाट रोड पर राजकुमार राय के मकान से अंजू देवी के मकान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक

देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में, प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो - 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार-पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।